LOK SABHA

Wednesday, August 30, 1978/Bhadra 8, 1900 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

राष्ट्रीय कपड़ा निगम को हुई हानि और इसका कार्यकरण

*510. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में राष्ट्रीय कपड़ा निगम (मध्य प्रदेश) के कार्यकरण के बारे में जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कार्यकरण में कोई अनियमितता पाई गई है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि इस निगम को मध्य प्रदेश में चलाई जा रही सात कपड़ा मिलों से डेढ़ करोड़ रुपये की हानि हो रही है;

(घ) क्या इस निगम के लेखों की लेख परीक्षा नहीं की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस निगम के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). राष्ट्रीय वस्त्र निगम (मध्य प्रदेश) लि० के कार्यकरण की कोई जांच नहीं की गई थी । किन्तु कुछ विशिष्ट शिकायतों के अनुसरण में राष्ट्रीय वस्त्र निगम (धारक कम्पनी) द्वारा जांच की गई थी । जांच से किसी प्रकार के अनियमितता की पुष्टि नहीं हो सकी है ।

(ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम (मध्य प्रदेश) लि० द्वारा चलाई जा रही सिविल मिल्स में हो रही हानि का सरकार को पता है । इस मिल में 1975–76 से अब तक हुई वर्ष-वार हानि का विवरण निम्नलिखित है :–

वर्ष	हानि (करोड़ रुपयों में)
1975–76	8.46 (लेखा परीक्षित)
1976–77	7.68 (अनन्तिम) (भुगतान की गई बोनस की 88.33 लाख रुपये की राशि निकालकर)
1977–78	5.27 (अनन्तिम)
1978–79 (अप्रैल से जून, 78)	1.20 (अनन्तिम)

(घ) राष्ट्रीय वस्त्र निगम (मध्य प्रदेश) लि० के वर्ष 1974–75 और 1975–76 के लेखों की पहले ही लेखा परीक्षा हो चुकी है और उन्हें स्वीकार किया जा चुका है । 1976–77 के लेखों की लेखा परीक्षा पूरी होने वाली है ।

(ङ) इन मिलों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए किए गए/किए जा रहे अभ्युपाय निम्नलिखित हैं :—

(i) मशीनों का आधुनिकीकरण / पुनर्नवीकरण;

(ii) केन्द्रीयकृत आधार पर कच्चे माल की इकट्ठी ज्यादा परिमाण में प्राप्ति;

(iii) उत्पादन पद्धति में विविधीकरण करना;

(iv) सुधरी हुई विपणन नीति;

(v) भारी हानि उठाने वाली मिलों का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण करना; और

(vi) कार्यभार और श्रमिक शक्ति का युक्तिकरण ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : माननीय मन्त्री जी ने जो विवरण सभा पटल पर रखा है इसमें जो हानि बतायी है वह इस प्रकार है कि 1975–76 में 8 करोड़ 46 लाख, 1976-77 में 7 करोड़ 68 लाख, इस प्रकार से घाटा बढ़ता आ रहा है । मेरा कहना है कि यह घाटा बढ़ा है, 7 करोड़ से ऊपर है । मैं इसके आंकड़े देना चाहता हूं :

मालवा मिल्स, इन्दौर में 16 लाख रु० का नुकसान है;

कल्याण मिल्स, इन्दौर में 9 लाख रु० का नुकसान;

स्वदेशी मिल्स, इन्दौर में 7 लाख रु० का नुकसान;

ताप्ती मिल्स, बरहानपुर में 3 लाख रु० का घाटा,

बंगाल काटन मिल्स, राजनन्दगांव में 10 लाख रु० का घाटा;

भोपाल टैक्सटाइल्स मिल्स में 8 लाख रु० का घाटा; और

हीरा मिल्स, उज्जैन में 8 लाख रु० का घाटा ।

यह घाटा कुल मिला कर 61 लाख का है ?

अब इन्होंने मेरे प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि वहां मजदूरों ने काम करने से इंकार कर दिया इसलिये वहां घाटा हो रहा है । मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि एन० टी० सी० की 7 मिलों में घाटा हो रहा है, ऐसा मन्त्री जी का कहना है । मेरा कहना है कि वहां पर जो 7 प्राइवेट मिल्स हैं उनमें करोड़ों रु० का मुनाफ़ा हो रहा है, और यह ऐसा समय है कि सब मिलें कमा रही हैं । इतना ही नहीं इन्दौर टैक्सट इल्स में जिसको हाल ही में मध्य प्रदेश शासन ने अपने हाथ में लिया है, प्रारम्भ के तीन, चार महीनों को छोड़ कर, डेढ़ लाख रु० से 3 लाख रु० प्रति माह का मुनाफ़ा हो रहा है । जबकि उसमें प्रोसेसिंग समान नहीं है । तो इनकी मिलें घाटे में जा रही हैं, जबकि प्राईवेट मिलें मुनाफ़ा कमा रही हैं, क्या मन्त्री जी को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि मध्य प्रदेश की एन० टी० सी० मिलें घाटे में हैं और माननीय सदस्य ने जो आंकड़े दिये हैं, वे भी बिल्कुल ही सही हैं, मगर एन० टी० सी० की कुल सबसीडियरीज में मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, वे दो हैं जो आज अधिक घाटे में चल रही हैं । सिर्फ निजी क्षेत्र के मिलों में ही मुनाफा होता है, एन० टी० सी० में घाटा होता है, ऐसी बात नहीं है । तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात, ये जो एन० टी० सी० की 4 सबसीडियरीज हैं, ये इस समय मुनाफे में चल रही हैं ।

पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के घाटे का जो सवाल है, इसके जो कारण मैंने पहले सदन में रखे हैं, वही कारण हैं जिनके बारे में

विचार करने की जरूरत है। हम अपनी तरफ से प्रयत्नशील हैं कि इन कारणों को दूर किया जाये। मध्य प्रदेश में 7 मिलों में कुल 21 हजार मजदूर हैं और उनमें से 4 हजार इस समय सरप्लस हैं। 4 हजार सरप्लस मजदूरों का मतलब है कि महीने में 25 लाख रुपये यानी साल भर में 3 करोड़ रुपये तनख्वाह हम दे रहे हैं जिसके लिये कोई उत्पादन हमें नहीं मिल रहा है।

मध्य प्रदेश के अन्य किसी निजी मिलों में या हिन्दुस्तान के सभी मिलों में एक मजदूर 4 लूम्स को देख रहा है। मध्य प्रदेश के हमारे एन० टी० सी० में एक बरहानपुर की मिल को छोड़ कर एक मजदूर सिर्फ दो ही लूम को देखने के लिये तैयार हैं। 1974 में एक एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट को अमल में लाने से वहां पर मजदूरों ने इंकार किया है। हम मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री, उद्योग मन्त्री, श्रम मन्त्री से निजी तौर पर मिले हैं, उनसे कहा है कि मजदूरों के संगठनों से बातचीत करो और इसमें से उचित रास्ता निकालो। अभी मध्यप्रदेश की सरकार से पता चला कि उन्होंने अपने लेबर कमिश्नर को बम्बई की मिलों को देखने के लिये कहा है। उनसे एन० टी० सी० के मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों को ले जाने को कहा। जो जानकारी मुझे मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मिली है, उससे पता चलता है कि यूनियन के नेता यह कहते हैं कि बम्बई में जाने का मतलब 4 लूम चलाने का है। इसके लिये हम तैयार नहीं। विशेष परिस्थिति मध्य प्रदेश में चल रही है। जहां सारे देश में एन० टी० सी० की मिलें, मुनाफे की ओर जा रही हैं, इस वक्त मध्य प्रदेश में घाटे में ही चल रही हैं और अगर यह सिलसिला इसी तरह से चलता रहा तो उस पर हमें फिर विचार करना पड़ेगा कि इन मिलों का भविष्य में क्या किया जाये।

श्री हुकम चन्द कछवाय : माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर कुछ घुमाफिराकर दिया है और सही जानकारी नहीं दी है। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता हूं कि मजदूरों ने 4 सांचे चलाने से इन्कार कर दिया। आखिर यह क्यों? उज्जैन में विनोद मिल, एन० टी० सी० इन्दौर टैक्सटाइल मिल, इन्दौर में हुकमचन्द मिल, राजकुमार मिल, भंडारी मिल, रतलाम में सज्जन मिल, ग्वालियर में जे० सी० मिल, इन सब में 4 सांचे चल रहे हैं। वहां चल रहें हैं या नहीं चल रहे हैं, आखिर कारण क्या हैं। एक ही पार्टी की यूनियन को मान्यता सारे प्रदेश के मिलों में है। हमने कहा कि पूरी सपोर्ट देंगे, आपको सहयोग देंगे, लेकिन हमारा सहयोग लेने से इन्कार कर दिया। इसकी आड़ में बहुत सी बातें हैं, मुझे जब भी समय मिलेगा, मैं सारी बातों का उल्लेख करूंगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि अधिकारी इस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? इसका कारण यह है कि एन० टी० सी० के चेयरमैन ने सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिये हैं, माल खरीदने का, बेचने का और स्टाक पर्चेज का काम सब उनके हाथ में है। किसी भी टैक्निकल अफसर को मिल के कंट्रोलर और प्रबंधक बदल नहीं सकते हैं, और उनका इन्ट्रेस्ट मिल को मुनाफे में लाने का नहीं है। गलत ढंग से अपने को लाभ पहुंचाते हैं। वहां के जो कंट्रोलर हैं, उनको कोई हक नहीं है कि उनको हटा सकें या किसी को एप्वाइन्टमैंट दे सकें। सारे अधिकार चेरमैन ने छीन लिये हैं। उसका परिणाम यह है कि यह अनियमिताएं हो रहीं हैं, किसी की कोई सुनता नहीं है। किसी को एप्वाइन्टमैंट देना हो तो यह करेंगे।

दूसरे मेरे प्रश्न के उत्तर में यह कहा है कि वहां कुछ मजदूरों की कुछ समस्याएं हैं आपने यह भी कहा कि कोई ग्रे कपड़ा नहीं बेचा है। मैं एक ही मिल का उदाहरण देना चाहता हूं। उज्जैन की हीरा मिल से जो ग्रे क्लाथ बेचा गया है, उसके आंकड़े इस प्रकार हैं— जनवरी, 1978 : 3,87,452 मीटर,

फरवरी, 1978 : 93,732 मीटर, मार्च, 1978 : 64,141 मीटर, अप्रैल, 1978 : 1,96,373 मीटर, मई, 1978 : 1,52,728 मीटर और जून, 1978 : 2,76,035 मीटर इस का टोटल है 11,70,461 मीटर । इतनी बड़ी मात्रा में ग्रे क्लाथ, हरा कपड़ा, इस बात के बावजूद बेचा गया है कि प्रासेसिंग प्लांट बहुत बड़ी क्षमता में लगे हुए हैं । उज्जैन में इन्दौर टेक्सटाइल मिल में प्रासेसिंग प्लांट नहीं है, मगर वह भी मुनाफा कमा रही है । मेरा कहने का मतलब यह है कि वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर अनियमिततायें हो रही हैं, जिससे बड़ा घाटा हो रहा है ।

मैंने पीछे एक प्रश्न पूछा था कि विदेशों में भेजने के लिए विभिन्न मिलों में कितना कितना कपड़ा बनाया गया । उस प्रश्न के उत्तर में सरकार की ओर से यह बताया गाया कि यह बताना सार्वजनिक हित में नहीं है । आज भी ऐसी पार्टियां हैं, जिन्होंने विदेशों में हजारों गांठे बेची हैं । साल से ऊपर हो गया है, मगर उन का पेमेंट आज तक एन० टी० सी० को नहीं हुआ है, जिसका डेमरेज और बैंक ब्याज हम भर रहे हैं ।

वहां पर ये जो अनियमितायें हो रही हैं, उन का मूल कारण है वहां का चेयरमैन । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह वर्तमान चेयरमैन को हटा कर कोई दूसरा आदमी वहां लायेंगे, ताकि पालिसी में परिवर्तन हो और मिलों को मुफा होने लगे । वर्तमान चेयरमैन की मंत्री महोदय का पूरा सहयोग और सपोर्ट प्राप्त है । जब वर्तमान चेयरमैन के विरुद्ध विभिन्न प्रश्न उठाये गये, तो उन्होंने मंत्री महोदय के पैर पकड़ लिये । उसके बाद मंत्री महोदय बराबर उन्हें अपना आशीवाद देते आ रहे हैं और उन के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं ।

श्री जार्ज फ़र्नान्डीस : माननीय सदस्य की चेयरमैन के बारे में और अन्य मसलों के बारे में जो राय है, उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है । उनका अपना एक दृष्टिकोण है और वह उसको रख कर चल सकते हैं । जहां तक घाटे का सवाल है, मैंने बताया कि इन मिलों में इस समय 21,000 मजदूरों में से 4,000 मजदूर आवश्यकता से अधिक हैं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : कैसे मालम हुआ ?

What was the basis of this assessment? Was there any physical verification?

श्री जार्ज फ़र्नान्डीस : इस बारे में अध्ययन हुआ है और उसकी रिपोर्ट हमारे पास है, जो एक निष्पक्ष रिपोर्ट है ।

जहां पूरे मध्य प्रदेश में, और समूचे देश में, स्पिनिंग मिलों में चार लूम्ज एक मजदूर चलाता है, वहां एन० टी० सी० की सात मिलों में से छः में सिर्फ दो लूम्ज चलाये जा रहे हैं । ताप्ती मिल में 1976–77 में सिर्फ 17 लाख रुपये का घाटा हुआ है । इस का कारण यह है कि वह मध्य प्रदेश में एन० टी० सी० की एक मिल है, जहां चार लूम्ज एक मजदूर चलाता है ।

दूसरा कारण यह है कि पिछले साल अक्तूबर से इस साल के जून महीने तक वहां पर 20 प्रतिशत बिजली की कटौती की गई थी, जो कि सारी टेक्सटाइल मिलों पर लागू की गई थी, और जुलाई से वह कटौती 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत कर दी गई है । मेरे पास एन० टी० सी० की मिलों के बारे में जुलाई के आंकड़े हैं । खाली मध्य प्रदेश में एन० टी० सी० में 45 लाख रुपये का घाटा है और पश्चिमी बंगाल में एन० टी० सी० में 57 लाख रुपये का घाटा है, जबकि सारे देश में एन० टी० सी० की मिलों में सिर्फ 31 लाख रुपये का घाटा है । 1974 से ले कर आज तक - एन० टी० सी० के बनने से ले कर आज तक--इतना बढ़िया मुनाफा एन० टी० सी० में कभी नहीं हुआ ह, जितना कि पिछले जुलाई मास में हुआ है । एन० टी० सी० गुजरात में मुनाफा

53 लाख रुपये, तामिलनाडु और पांडीचेरी में 49 लाख, एन० टी० सी०, आंध्र प्रदेश में 12 लाख और एन० टी० सी०, उत्तर प्रदेश में 2 लाख पये का मुनाफा हुआ है। लेकिन एन० टी० सी० मध्य प्रदेश में 45 लाख रुपये और एन० टी० सी०, पश्चिमी बंगाल में 57 लाख रुपये का घाटा हुआ है। जो स्वदेशी मिलें पहले घाटे में चल रही थी, जब से सरकार ने उन्हें अपने हाथ में लिया है, तब से उनमें 23 लाख रुपये का मुनाफा हुआ है। जुलाई महीने में उन्होंने इतना रेकार्ड प्राफिट दिया—23 लाख नेट।

इसलिए मध्य प्रदेश का जो मामला है उस मामले को वहां दरअसल जो बातें हैं, मिलों को चलाने की जो बात है, वहां की प्रोडक्टिविटी का जो सवाल है, बिजली का जो मामला है, इन सारे मामलों को दुर्लक्ष्य कर के चेयरमैन या किसी अफसर के नाम से ही किसी माननीय सदस्य को आक्षेप उठाना हो तो मैं इस की कोई सफाई दे नहीं सकता हूं। अगर वहां के मजदूरों की कोई समस्या है जो एन टी सी के और मजदूरों के साथ जुड़ी हुई है तो उस को हल करने के लिए मैं तैयार हूं।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मेरा जवाब नहीं आया। मैंने पूछा था कि जो गलत मालिसी बनी है परचेज की, माल खरीदने और बेचने की, सारा सामान चेयरमैन खरीदते हैं और बेचते हैं। इस का उत्तर नहीं आया...

श्री जार्ज फर्नान्डीस : दूसरा कोई तथ्य नहीं हैं। हर काम के लिए नियुक्त अधिकारी हैं वे लोग अपना काम करते हैं।

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या यह सही है कि मध्य प्रदेश की एन टी सी मिलों के पास लगभग 35 हजार गांठें बिना बिके पड़ी हैं जिन का मूल्य करीब 8 करोड़ रुपये होता है और क्या यह भी सही है कि उन्होंने कुछ ऐसा कपड़ा जो एक ही क्वालिटी का था उस को किन्हीं व्यापारियों को 2 रुपया 18 पैसे मीटर और कुछ किन्हीं दूसरे व्यापारियों को 2 रुपये 4 पैसे मीटर बेचा है और इसी प्रकार से कुछ अन्य उदाहरण भी हैं जिन में खरीद और बिक्री में अनियमितताएं बढ़ती गई हैं। अनेक बातें हैं। कपड़े के थान पर 9 मीटर लिखा होता है किन्तु कई बार 8 मीटर निकलता है, जिन के कारण मध्य प्रदेश की मिलों को निरन्तर घाटा हो रहा है और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है चेयरमैन के सम्बन्ध में, क्या वे दोषी हैं या दूसरे अधिकारी दोषी हैं, इस बात की कोई जानकारी आप ने प्राप्त की है? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या चेयरमैन की नियुक्ति के समय मध्य प्रदेश राज्य सरकार से सलाह या परामर्श ली गई थी और उस के बाद उन की नियुक्ति की गई थी?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : चेयरमैन की नियुक्ति जनवरी 1977 में हुई थी। मुझे मालूम नहीं कि उस समय राज्य सरकार से सलाह मशविरा हुआ था या नहीं हुआ था। मैं इस की जानकारी ले लूंगा। जहां तक कपड़ा किस दाम में बेचा गया, किस दाम में चीजें खरीदी गई, इस में कहां तक अनियमितताएं हुई हैं, इस के बारे में कई शिकायतें आई हैं। उन सारी शिकायतों पर हम ने जांच की है। हमें उस जांच से ऐसी कोई चीज मिली नहीं है जिस से हम यह कह सकें कि इस में किसी तरह का भी गलत काम हुआ है।

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : वह जो गांठें बिना बिकी हुई पड़ी हैं उस का उत्तर नहीं आया। कृपया इस मामले में गहराई से जांच करें।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हमारे पास इस की कोई जानकारी नहीं है। मैं इस की जानकारी हासिल करूंगा।

SHRI DINEN BHATTACHARYA: In the reply given by the hon. Minister he has stated that the NTC mills in West Bengal have incurred a loss of Rs. 57 lakhs in the month of July. May I know whether it is a fact that in most of the mills in West Bengal as in Madhya Pradesh, during the previous regime, thousands of workers were given employment by the Congress Ministers and those workers have still no work. Are you going to...

AN HON. MEMBER: This is irrelevant.

SHRI DINEN BHATTACHARYA: Why irrelevant? All goonda elements have been appointed there. I am making this statement with a full sense of responsibility. If any one wants to challenge, come to me, I will show you. Are you going to institute an inquiry into the working conditions in West Bengal? If you go to any mill, you will find that there is no cotton, no raw material and the managements were connected with the previous Government. Are you going to institute an inquiry by an impartial agency or by your Government?

SHRI GEORGE FERNANDES: I have no evidence in my possession; nor has anyone ever made this charge so far that workers have been recruited for political considerations in the NTC Mills in West Bengal.

In so far as the Hon. Member's suggestion about an enquiry into the working of the NTC Mills is concerned, I have set up a Committee of Trade Unionist representatives of Central organisations. I have set up the Committee of Trade Unionist representatives to investigate and report on the working of all the NTC Mills in the country, including the West Bengal NTC Mills. I have also told the Textile Trade Union leaders of West Bengal that if they wish to constitute a special Task Force to study the working of the NTC Mills in West Bengal and come forward with any recommendations that would enable us to run the mills profitably, I will accept the recommendations. (*Interruptions*).

श्री उपसेन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय हुकम चन्द कछवाय जी ने मध्य प्रदेश के एन टी सी के गड़बड़ घोटाले के बारे में अभी हाल में प्रेस में एक बयान दिया था, मैं माननीय मन्त्री जी का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं क्या उनका ध्यान कछवाय जी के उस स्पष्ट वक्तव्य की ओर गया है ? यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कछवाय जी का बयान हमने देखा है जो पिछली फरवरी और उसके बाद मई में आया था, जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश के एन टी सी में बहुत गड़बड़ घोटाला है, उसके लिए वहां के चेयरमैन जिम्मेदार हैं और उसके लिए उद्योग मंत्री भी जिम्मेदार हैं। उद्योग मंत्री को, कछवाय जी के अनुसार, वहां के चेयरमैन एक लाख रुपया घूस भी देते हैं। यह बात उन्होंने अपने बयान में कही है। हमने इस मामले को प्रधान मंत्री के पास भेज दिया और कहा आप इस की जांच करावायें। प्रधान मंत्री जी ने उस पर जांच करके कह दिया कि यह बिल्कुल निराधार है। हमने इस मामले को ला मिनिस्टर के पास भेजा है ताकि इसमें जो भी कानूनी कार्यवाही होनी है वह हो जाये। मैं श्री दीनेन भट्टाचार्य और श्री हुकम चन्द कछवाय जी से इतना ही कहूंगा कि इस सदन के किन्हीं भी सदस्यों की एक कमेटी बनावें और इस मामले की जांच करावायें और अगर इसमें से एक शब्द भी सच निकले तो मैं राजनीतिक जीवन से हट जाऊंगा वरना जो आरोप लगाने वाले हैं वे क्षमा मांगें—मैं उन और किसी चीज की अपेक्षा नहीं करूंगा

Notifications of tribal areas in Andhra Pradesh

*513. SHRI G. NARASIMHA REDDY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there are a good number of villages in